

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	फाल्गुन 24, गुरुवार, शाके 1945-मार्च 14, 2024 Phalguna 24, Thursday, Saka 1945- March 14, 2024	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज़ायें।

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी एवम उपखण्ड अधिकारी लाखेरी जिला बून्दी

अधिसूचना

बून्दी, फरवरी 06, 2024

(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापनमें उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4(1))

भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापनमें उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के तहत राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापनमें उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार 2016 के प्रावधानुसार एवम राजस्थान सरकार के राजस्व ग्रुप-6 विभाग के परिपत्र क्रमांक प01 150 राज0/6/2016/02 दिनांक 27.01.2017 के निर्देशानुसार बून्दी जिले की तहसील इन्देर्गढ़ (ग्राम- खरायता, लबान, रामगंज) एल.सी.नंबर 136 पर रेल्वे आर्वर ब्रिज निर्माण में निम्नानुसार प्रभावित गाँवोंमें भूमि अर्जन किया जाना प्रस्तावित है।

ग्राम- खरायता विवरण

क्र.सं.	खसरासं.	कुलरकबा (है०)	अवाप्त किए जाने वाला क्षेत्रफल (है०)
1	2	3	4
1	635	1.390	0.0135
2	636	0.100	0.0237
3	637	0.140	0.1383
4	638	0.150	0.0232
5	640	1.760	0.0100
6	642	0.040	0.0146
7	643	0.550	0.3570
8	644	1.800	0.0890
9	649	0.070	0.0001
10	653	2.220	0.0500
11	659	0.150	0.0396
12	661	0.450	0.0005
13	720	1.000	0.0735
14	722	0.350	0.0532
15	723	0.080	0.0199
16	727	0.880	0.2122
17	728	1.000	0.1652
18	737	1.550	0.1077
19	738	0.020	0.0196
20	739	0.570	0.0156

21	740	0.020	0.0100
22	743	0.460	0.0020
23	641/1	0.250	0.0002
24	641/2	0.380	0.0044
25	648/747	0.450	0.0091
26	816/718	0.350	0.0125
27	829/741	0.110	0.0020
28	830/741	1.820	0.0020
29	857/660	0.200	0.0575
30	858/660	0.200	0.1130
योग	किता 30		1.6391

ग्राम – लबान विवरण

क्र.सं.	खसरासं.	कुलरकबा (है०)	अवाप्तकिए जाने वाला क्षेत्रफल (है०)
1	2	3	4
1	17/1449	0.060	0.0200
2	17/1451	0.020	0.0060
3	18	0.200	0.0020
योग	किता 3		0.028

ग्राम – रामगंज विवरण

क्र.सं.	खसरासं.	कुलरकबा (है०)	अवाप्तकिए जाने वाला क्षेत्रफल (है०)
1	2	3	4
1	92	0.490	0.002
2	91	0.140	0.0150
3	93	0.100	0.0140
4	102	4.000	0.0360
योग	किता 4		0.067

- अधिसूचित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम 2013 (अधिनियम संख्या ३०/२०१३) में उचित क्षतिपूर्ति और पारदर्शिता के अधिकार की धारा 11(1) के प्रावधानों के तहत की जाएगी।
- सरकार द्वारा अधिशाषी अभियन्ता, सा०नि०वि० खण्डलाखेरी व उनके स्टाफ/कर्मचारी को इलाके में किसी भी भूमि का सर्वे, नाप व लेवल के लिए प्रवेश करने, भूमि के नीचे मिट्टी की जांच के लिए बोरकरने व परियोजना के किर्यान्वन व उचित निर्माण के लिए अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत वर्णित प्रावधानों के अनुसार प्राधिकृत किया जाता है।

- भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता के अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11(4) के अनुसार कोई भी व्यक्ति ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख के अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को पूरा होनेके समय तक प्रारम्भिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का जिला कलेक्टर महोदय की अनुमति के बिना कोई सव्यवहार नहीं करेगा या कोई सव्यवहार कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।
- परियोजना हेतु नियमानुसार सामाजिक समाघात निर्धारण हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड लाखेरी द्वारा सामाजिक समाघात हेतु एजेन्सी का चयन करवाया जायेगा।
- सामाजिक समाघात निर्धारण हेतु चयनित संस्था द्वारा परियोजना हेतु प्रस्तावित भू-अर्जन से प्रभावित गाँवों में सामाजिक समाघात निर्धारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार 2016 के प्रावधानुसार किया जावेगा। सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी।
 1. संस्थान द्वारा परियोजना हेतु प्रस्तावित भूमि अर्जन से प्रभावित व्यक्तियों का विवरण तैयार कर सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रारूप रिपोर्ट तैयार की जायेगी।
 2. प्रारूप रिपोर्ट की प्रति प्रभावित गाँवों में समुचित स्थान पर प्रदर्शित की जावेगी तत्पश्चात प्रभावित गाँवों में पर्याप्त प्रचार-प्रसार के उपरान्त जनसुनवाई की जावेगी जिसका कार्यवाही विवरण समुचित रूप से रिकार्ड किया जावेगा।
 3. जनसुनवाई के दौरान आये सुझावों/ आपतियों के समुचित समाधान को शामिल कर सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवम सामाजिक समाघात प्रबन्ध रिपोर्ट तैयार की जावेगी।
 4. सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रक्रिया प्रभावित गाँवों में सम्बंधित पंचायत/नगरपालिका के परामर्श से की जावेगी।
 5. सामाजिक समाघात मूल्यांकन के दौरान किसी भी प्रकार के बल प्रयोग या धमकी का प्रयत्न इस कवायद का अक्रत और शूल्य बना देगा।
 6. सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रिया को इस अधिसूचना की तिथि से अधिकतम 6 माह की अवधि में पूर्ण सम्पूर्ण कराया जाना अनिवार्य है।

सुनील गुप्ता,
सयुक्त सचिव (पथ),
सा.नि.वि.राज.जयपुर।